



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092024-257118
CG-DL-E-12092024-257118

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3582]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 12, 2024/भाद्र 21, 1946

No. 3582]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 2024/BHADRA 21, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2024

का.आ. 3917(अ).—यतः, मै. महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने गाँव सुरवादी और नंदाल, तालुका फलटन, जिला सतारा, महाराष्ट्र राज्य में इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 04.08.2010 और दिनांक 30.10.2017 द्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में क्रमशः 101.25 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था और बाद में उक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र में 48.1695 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित किया था;

और यतः, मै. महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने अब उपर्युक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र के 53.0805 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पत्र संख्या एसईजेड-2022/सीआर-106/उद्योग-2 दिनांक 27 जुलाई, 2023 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। अनधिसूचना के बाद, भूमि पार्सल का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा, जो मूल रूप से कल्पित विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य की पूर्ति करेगा। अनधिसूचना के बाद, भूमि पार्सल का उपयोग, राज्य सरकार के भूमि उपयोग दिशानिर्देशों/मास्टर प्लान के अनुरूप होंगे;

और यतः, विकास आयुक्त, सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र ने उक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र के 53.0805 हेक्टेयर के पूरे क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अतः अब केंद्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ. 2/224/2007-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2024

S.O. 3917(E).—Whereas, M/s. Maharashtra Industrial Development Corporation Limited had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Engineering sector at Village Survadi and Nandal, Taluka Phaltan, District Satara, in the State of Maharashtra;

AND, WHEREAS, the Central Government, in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 101.25 hectares and later de-notified an area of 48.1695 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification dated 04.08.2010 and dated 30.10.2017, respectively;

AND, WHEREAS, M/s. Maharashtra Industrial Development Corporation Limited has now proposed to de-notify the entire area of 53.0805 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Maharashtra has given No Objection Certificate to the proposal vide letter No. SEZ-2022/CR-106/Ind-2 dated 27th July, 2023. After de-notification, the de-notified parcels of land will be utilised toward creation of infrastructure which would sub-serve the objective of the SEZ as originally envisaged. The State Govt. also certified that the de-notified parcels of land will conform to land use guidelines/master plan of the State Government;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, SEEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 53.0805 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in the exercise of the powers conferred by the first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except for things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F. 2/224/2007-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.